ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor = 8.35, January-June 2026, Submitted in January 2026

नई आर्थिक नीति एवं भारतीय अर्थव्यवस्था

पूनम, शोधार्थी, (अर्थशास्त्र विभाग), टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर
डॉ0 रणधीर सिंह, सहायक आचार्य, (अर्थशास्त्र विभाग), टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर
Email ID: randheer1007@gmail.com

शोध सारांश

नई आर्थिक नीति, 1991 के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, कार्यप्रणाली तथा विकास की दिशा में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला। इस नीति का मूल आधार उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण था, जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था को अत्यधिक नियंत्रित व्यवस्था से निकालकर अधिक प्रतिस्पर्धात्मक, बाजारोन्मुख तथा वैश्विक आर्थिक व्यवस्था से संबद्ध करने का प्रयास किया गया। प्रस्तुत शोध में नई आर्थिक नीति के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े बहुआयामी प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य यह समझना है कि आर्थिक उदारीकरण के पश्चात उत्पादन, निवेश, औद्योगिक विकास, व्यापार, विदेशी पूंजी, सेवा क्षेत्र, रोजगार तथा आर्थिक वृद्धि की प्रकृति में किस प्रकार परिवर्तन आया। नई आर्थिक नीति ने निजी क्षेत्र की भूमिका को व्यापक बनाया तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए नए अवसर उपलब्ध कराए। इसके परिणामस्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और अन्य सेवा क्षेत्रों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ। साथ ही, भारतीय उद्योगों के समक्ष वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जिसके कारण तकनीकी उन्नयन, उत्पादकता और प्रबंधन क्षमता में सुधार की आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण हुई। तथापि, नीति के प्रभाव समान रूप से सकारात्मक नहीं रहेय क्षेत्रीय असमानता, आय–विषमता, रोजगार की गुणवत्ता, कृषि क्षेत्र की चुनौतियाँ तथा छोटे एवं परंपरागत उद्यमों पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव जैसी समस्याएँ भी सामने आईं। अतः शोध यह प्रतिपादित करता है कि नई आर्थिक नीति को केवल आर्थिक वृद्धि की दृष्टि से नहीं, बल्कि समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और रोजगार सृजन के व्यापक संदर्भ में देखना आवश्यक है।

अध्ययन के विश्लेषण से यह निष्कर्ष उभरता है कि नई आर्थिक नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अधिक गहराई से जोड़ने तथा विकास की नई संभावनाएँ निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदारीकरण के पश्चात बाजार–व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, निजी निवेश को प्रोत्साहन मिला और अनेक क्षेत्रों में तकनीकी तथा संस्थागत परिवर्तन तेज हुए। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास प्रक्रिया में सेवा क्षेत्र का योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा, जबकि विनिर्माण तथा कृषि क्षेत्र में अपेक्षित संतुलित प्रगति सुनिश्चित करना अभी भी एक प्रमुख नीतिगत चुनौती है। वैश्वीकरण ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अवसर बढ़ाए, किंतु इसके साथ वैश्विक आर्थिक उतार–चढ़ाव के प्रति भारतीय अर्थव्यवस्था की संवेदनशीलता भी बढ़ी। शोध से यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक सुधारों की सफलता का मूल्यांकन केवल सकल घरेलू उत्पाद या निवेश वृद्धि जैसे संकेतकों के आधार पर नहीं किया जा सकताय इसके लिए रोजगार, प्रति व्यक्ति आय, गरीबी में कमी, मानव विकास, आय–वितरण, क्षेत्रीय संतुलन तथा सामाजिक सुरक्षा जैसे मानकों को भी सम्मिलित करना आवश्यक है। भविष्य की आर्थिक नीति में बाजार की दक्षता और राज्य की सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक होगा। विशेष रूप से कृषि, लघु एवं मध्यम उद्यम, कौशल विकास, रोजगार, आधारभूत संरचना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किए बिना व्यापक और समावेशी आर्थिक विकास प्राप्त करना कठिन है। इस प्रकार नई आर्थिक नीति भारतीय अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण की महत्वपूर्ण आधारशिला सिद्ध हुई है, किंतु इसके दीर्घकालीन लाभों को व्यापक सामाजिक वर्गों तक पहुँचाने के लिए समावेशी, रोजगारपरक, संतुलित और सतत आर्थिक नीतियों की निरंतर आवश्यकता बनी हुई है।

शोध कुंजी :
नई आर्थिक नीति, भारतीय अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, आर्थिक सुधार, आर्थिक विकास, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूंजी निवेश, औद्योगिक विकास, सेवा क्षेत्र, रोजगार, आर्थिक असमानता, समावेशी विकास, सतत आर्थिक विकास।

शोध की प्रस्तावना

भारतीय अर्थव्यवस्था का विकासक्रम स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक नीतिगत परिवर्तनों से गुजरा है। स्वतंत्रता के प्रारंभिक दशकों में देश ने नियोजित आर्थिक विकास, सार्वजनिक क्षेत्र की प्रधानता, औद्योगिक नियंत्रण तथा आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनाकर आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के

निर्माण का प्रयास किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विकास, कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा सार्वजनिक संस्थानों के विस्तार को विशेष प्राथमिकता दी गई। यद्यपि इस मॉडल ने औद्योगिक आधार और संस्थागत संरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, तथापि समय के साथ लाइसेंस–परमिट व्यवस्था, उत्पादन एवं निवेश पर नियंत्रण, राजकोषीय दबाव, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों तथा अपेक्षाकृत धीमी आर्थिक वृद्धि जैसी समस्याएँ उभरने लगीं। वर्ष 1990–91 में भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर भुगतान संतुलन संकट से प्रभावित हुई, जिसने आर्थिक नीति की दिशा में व्यापक पुनर्विचार की आवश्यकता उत्पन्न की। इसी ऐतिहासिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि में वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति को लागू किया गया, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक उदार, प्रतिस्पर्धात्मक और बाजारोन्मुख स्वरूप प्रदान करने की प्रक्रिया को गति दी। नई आर्थिक नीति के प्रमुख आधार उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण रहे, जिनका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों पर अनावश्यक सरकारी नियंत्रण को कम करना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ना था।

नई आर्थिक नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना और कार्यप्रणाली में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किए। औद्योगिक लाइसेंसिंग में कमी, विदेशी निवेश के लिए अवसरों का विस्तार, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में पुनर्संरचना, व्यापार नीति में उदारीकरण तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधारों ने आर्थिक गतिविधियों के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्मित किया। इसके परिणामस्वरूप निजी निवेश, तकनीकी हस्तांतरण, विदेशी पूंजी, निर्यात तथा सेवा क्षेत्र के विकास को नई गति प्राप्त हुई। विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और अन्य आधुनिक सेवा क्षेत्रों में भारत की वैश्विक उपस्थिति मजबूत हुई। आर्थिक सुधारों ने उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं के विकल्पों का विस्तार किया तथा अनेक उद्योगों में प्रतिस्पर्धा के माध्यम से गुणवत्ता और उत्पादकता सुधारने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया। दूसरी ओर, नई आर्थिक नीति के प्रभावों का मूल्यांकन केवल आर्थिक वृद्धि के आधार पर करना पर्याप्त नहीं है। कृषि क्षेत्र की संरचनात्मक समस्याएँ, असंगठित रोजगार, क्षेत्रीय असमानताएँ, आय–विषमता, छोटे एवं मध्यम उद्यमों पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव तथा विकास के लाभों के असमान वितरण जैसी चुनौतियाँ भी आर्थिक सुधारों के साथ समानांतर रूप से सामने आईं। अतः नई आर्थिक नीति का अध्ययन आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक एवं क्षेत्रीय समावेशन के संदर्भ में भी आवश्यक हो जाता है।

वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिवेश में भारतीय अर्थव्यवस्था पहले की तुलना में अधिक व्यापक रूप से अंतरराष्ट्रीय व्यापार, पूंजी प्रवाह, तकनीकी परिवर्तन और वैश्विक बाजारों से जुड़ी हुई है। इस परिवर्तन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने नए अवसरों के साथ–साथ नई चुनौतियाँ भी प्रस्तुत की हैं। वैश्विक मंदी, आपूर्ति–श्रृंखला में व्यवधान, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय अस्थिरता, तकनीकी परिवर्तन और रोजगार के बदलते स्वरूप जैसी परिस्थितियाँ आर्थिक नीति को अधिक गतिशील और उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। इस संदर्भ में नई आर्थिक नीति के दीर्घकालीन प्रभावों का पुनर्मूल्यांकन विशेष महत्व रखता है। शोध के स्तर पर यह जानना आवश्यक है कि आर्थिक उदारीकरण से प्राप्त वृद्धि के लाभ किस सीमा तक विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक वर्गों तक पहुँचे हैं तथा आर्थिक सुधारों ने रोजगार, निवेश, उत्पादन, व्यापार और जीवन–स्तर को किस प्रकार प्रभावित किया है। साथ ही, यह भी विचारणीय है कि आर्थिक वृद्धि और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए राज्य की भूमिका किस प्रकार विकसित हुई है। इस प्रकार नई आर्थिक नीति भारतीय आर्थिक इतिहास में केवल एक नीतिगत परिवर्तन नहीं, बल्कि आर्थिक संरचना, बाजार व्यवस्था और विकास–दृष्टिकोण में आए व्यापक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है।

प्रस्तुत शोध का केंद्र नई आर्थिक नीति और भारतीय अर्थव्यवस्था के पारस्परिक संबंध का विश्लेषण करना है। अध्ययन के माध्यम से नई आर्थिक नीति की पृष्ठभूमि, प्रमुख विशेषताओं, उद्देश्यों तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभावों को व्यवस्थित रूप से समझने का प्रयास किया गया है। इसमें आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक विकास, पूंजी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, व्यापार, सेवा क्षेत्र, रोजगार तथा समावेशी विकास जैसे प्रमुख आयामों को विश्लेषण का आधार बनाया जा सकता है। अध्ययन का व्यापक उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि नई आर्थिक नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार परिवर्तित किया तथा इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न अवसरों और चुनौतियों का स्वरूप क्या रहा। इस दृष्टि से नई आर्थिक नीति की उपलब्धियों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करते हुए उसकी सीमाओं और सामाजिक–आर्थिक प्रभावों को भी समझना आवश्यक है। अंततः अध्ययन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि आर्थिक सुधारों की वास्तविक

सफलता केवल उच्च आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने में नहीं, बल्कि ऐसी विकास प्रक्रिया निर्मित करने में निहित है जो रोजगारपरक, समावेशी, संतुलित और सतत हो। इसलिए नई आर्थिक नीति का अध्ययन भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को समझने के साथ–साथ भविष्य की आर्थिक नीति के लिए अधिक प्रभावी और जनोन्मुख दिशा निर्धारित करने की दृष्टि से भी अत्यंत प्रासंगिक है।

शोध के सोपान

विषय का चयन एवं समस्या की पहचान : इस सोपान में "नई आर्थिक नीति एवं भारतीय अर्थव्यवस्था" विषय का चयन करते हुए भारतीय आर्थिक व्यवस्था में 1991 के पश्चात हुए नीतिगत परिवर्तनों को अध्ययन की केंद्रीय समस्या के रूप में निर्धारित किया गया है। नई आर्थिक नीति के अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से उत्पन्न आर्थिक परिवर्तनों तथा उनके भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को अध्ययन का प्रमुख आधार बनाया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य एवं परिकल्पना का निर्धारण :इस चरण में शोध के प्रमुख उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है, जिनमें नई आर्थिक नीति की पृष्ठभूमि एवं स्वरूप का अध्ययन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों का विश्लेषण तथा आर्थिक वृद्धि, निवेश, औद्योगिक विकास, रोजगार और व्यापार में हुए परिवर्तनों का मूल्यांकन प्रमुख हैं। आवश्यकता के अनुसार अध्ययन की दिशा स्पष्ट करने के लिए संबंधित परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है।

साहित्य एवं स्रोत सामग्री का संकलन : इस सोपान में विषय से संबंधित पुस्तकों, शोध–प्रबंधों, शोध–पत्रों, सरकारी आर्थिक रिपोर्टों, आर्थिक सर्वेक्षणों, बजट दस्तावेजों तथा विश्वसनीय प्रकाशित स्रोतों का अध्ययन किया गया है। उपलब्ध साहित्य के माध्यम से नई आर्थिक नीति के सैद्धान्तिक आधार तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में उसके व्यावहारिक प्रभावों को समझने का प्रयास किया गया है।

तथ्यों एवं आँकड़ों का संकलन : इस चरण में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आवश्यक आर्थिक तथ्यों एवं सांख्यिकीय आँकड़ों को व्यवस्थित रूप से संकलित किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद, औद्योगिक उत्पादन, विदेशी निवेश, व्यापार, पूंजी निर्माण, रोजगार तथा अन्य संबंधित आर्थिक संकेतकों को अध्ययन के लिए उपयोगी आधार माना गया है।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या : संकलित तथ्यों और आँकड़ों का तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से परीक्षण किया गया है। नई आर्थिक नीति के पूर्व और पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए प्रमुख परिवर्तनों को विभिन्न आर्थिक संकेतकों के माध्यम से समझने का प्रयास किया गया है। सकारात्मक उपलब्धियों के साथ–साथ आर्थिक असमानता, रोजगार, कृषि तथा क्षेत्रीय विकास जैसी चुनौतियों को भी विश्लेषण में सम्मिलित किया गया है।

निष्कर्ष एवं सुझाव : अंतिम सोपान में प्राप्त तथ्यों के आधार पर अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों को प्रस्तुत किया गया है। नई आर्थिक नीति की उपलब्धियों एवं सीमाओं का समग्र मूल्यांकन करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक समावेशी, रोजगारपरक, संतुलित एवं सतत बनाने के लिए आवश्यक नीतिगत सुझावों को रेखांकित किया गया है।

शोध का महत्व

नई आर्थिक नीति एवं भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 1991 में लागू आर्थिक सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, दिशा और कार्यप्रणाली में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के माध्यम से अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक एवं बाजारोन्मुख बनाने का प्रयास किया गया, जिसके परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र, विदेशी निवेश, अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा तकनीकी विकास की भूमिका में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस अध्ययन के माध्यम से यह समझने में सहायता मिलती है कि आर्थिक सुधारों ने भारत की आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक विकास, पूंजी निर्माण, उत्पादन, व्यापार और सेवा क्षेत्र को किस प्रकार प्रभावित किया। नई आर्थिक नीति के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण अधिक तीव्र हुआ तथा भारतीय उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के नए अवसर प्राप्त हुए। इसलिए इस विषय का अध्ययन भारतीय आर्थिक विकास की वर्तमान स्थिति को समझने तथा पिछले तीन दशकों से अधिक समय में हुए आर्थिक परिवर्तनों का मूल्यांकन करने की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है।

नई आर्थिक नीति के महत्व का एक अन्य प्रमुख पक्ष भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता से संबंधित है। वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी बाजारों, पूंजी, तकनीक और ज्ञान के नए अवसर उपलब्ध कराए, किंतु इसके साथ वैश्विक आर्थिक संकटों, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उतार–चढ़ाव

तथा विदेशी पूंजी पर निर्भरता जैसी चुनौतियाँ भी बढ़ीं। अतः इस अध्ययन के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्विक आर्थिक परिवर्तनों के प्रति संवेदनशीलता तथा अनुकूलन क्षमता का मूल्यांकन किया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और अन्य सेवा क्षेत्रों के विकास ने भारत की आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है, जबकि विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों के समक्ष अभी भी अनेक संरचनात्मक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। इस प्रकार अध्ययन विभिन्न क्षेत्रों के विकास में उत्पन्न असंतुलन को पहचानने तथा संतुलित आर्थिक विकास के लिए आवश्यक नीतिगत प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में सहायक सिद्ध होता है।

शैक्षणिक एवं शोध की दृष्टि से भी इस विषय का विशेष महत्व है। नई आर्थिक नीति भारतीय अर्थव्यवस्था के संक्रमणकालीन विकास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र प्रस्तुत करती है, जिसमें राज्य की भूमिका, बाजार की शक्तियों, निजी क्षेत्र, वैश्विक पूंजी तथा सामाजिक कल्याण के बीच बदलते संबंधों का विश्लेषण किया जा सकता है। यह अध्ययन भविष्य के शोधकर्ताओं को आर्थिक सुधारों के दीर्घकालीन प्रभावों, क्षेत्रवार विकास, रोजगार संरचना, निवेश प्रवृत्तियों तथा समावेशी विकास से संबंधित अनुसंधान के लिए आधार प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त, अध्ययन से यह स्पष्ट करने में सहायता मिलती है कि आर्थिक सुधारों की सफलता का आकलन केवल सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से नहीं, बल्कि मानव विकास, रोजगार सृजन, आय–वितरण, सामाजिक सुरक्षा और जीवन–स्तर जैसे व्यापक मानकों के आधार पर किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से "नई आर्थिक नीति एवं भारतीय अर्थव्यवस्था" का अध्ययन भारतीय आर्थिक परिवर्तन को ऐतिहासिक, संरचनात्मक, सामाजिक और नीतिगत परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए अत्यंत प्रासंगिक एवं उपयोगी है।

शोध के उद्देश्य

- नई आर्थिक नीति की पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
- नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करना।
- नई आर्थिक नीति के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का विश्लेषण करना।
- पूंजी निवेश एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर नई आर्थिक नीति के प्रभाव का अध्ययन करना।
- भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में आए परिवर्तनों का विश्लेषण करना।
- कृषि क्षेत्र पर नई आर्थिक नीति के प्रभाव का अध्ययन करना।
- सेवा क्षेत्र के विकास में नई आर्थिक नीति की भूमिका का मूल्यांकन करना।
- रोजगार एवं श्रम बाजार पर आर्थिक सुधारों के प्रभाव का अध्ययन करना।
- नई आर्थिक नीति और वैश्वीकरण के पारस्परिक संबंध का विश्लेषण करना।
- आर्थिक विकास एवं आय–वितरण पर नई आर्थिक नीति के प्रभाव का अध्ययन करना।
- नई आर्थिक नीति से उत्पन्न प्रमुख उपलब्धियों एवं चुनौतियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- भारतीय अर्थव्यवस्था के समावेशी एवं सतत विकास के लिए नई आर्थिक नीति की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना।

शोध का निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि नई आर्थिक नीति, 1991 भारतीय अर्थव्यवस्था के विकासक्रम में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी चरण सिद्ध हुई। आर्थिक संकट की परिस्थितियों में प्रारंभ किए गए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूर्ववर्ती अधिक नियंत्रित व्यवस्था से निकालकर अपेक्षाकृत खुली, प्रतिस्पर्धात्मक और बाजारोन्मुख व्यवस्था की ओर अग्रसर किया। औद्योगिक लाइसेंसिंग में कमी, निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता, विदेशी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तथा व्यापारिक प्रतिबंधों में क्रमिक कमी ने आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के लिए नए अवसर उत्पन्न किए। इन सुधारों के परिणामस्वरूप निवेश, उत्पादन, व्यापार, तकनीकी विकास तथा सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिले। भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव भी पहले की तुलना में अधिक व्यापक हुआ। विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और अन्य आधुनिक सेवा क्षेत्रों ने आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार नई आर्थिक

नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक दिशा को बदलने तथा उसकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि नई आर्थिक नीति के प्रभावों को केवल आर्थिक वृद्धि की उपलब्धियों के आधार पर पूर्णतः सकारात्मक अथवा नकारात्मक नहीं माना जा सकता। आर्थिक सुधारों ने विकास के नए अवसरों का निर्माण किया, किंतु उनके लाभों का वितरण विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों में समान रूप से नहीं हुआ। कृषि क्षेत्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, लघु एवं मध्यम उद्योग तथा असंगठित क्षेत्र को अनेक प्रतिस्पर्धात्मक और संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आर्थिक विकास के साथ आय–विषमता, क्षेत्रीय असंतुलन, गुणवत्तापूर्ण रोजगार की कमी तथा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित प्रश्न भी महत्वपूर्ण बने रहे। इससे यह तथ्य सामने आता है कि उच्च आर्थिक वृद्धि अपने आप में समावेशी विकास की गारंटी नहीं देती। आर्थिक सुधारों की वास्तविक सफलता का मूल्यांकन रोजगार सृजन, गरीबी में कमी, मानव विकास, आय–वितरण, सामाजिक सुरक्षा तथा क्षेत्रीय संतुलन जैसे व्यापक मानकों के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

नई आर्थिक नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को आधुनिक, प्रतिस्पर्धात्मक और वैश्विक स्वरूप प्रदान करने में आधारभूत भूमिका निभाई, लेकिन आर्थिक सुधारों की अगली दिशा को अधिक समावेशी एवं संतुलित बनाने की आवश्यकता है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगारपरक निवेश बढ़ाना, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रदान करना, कौशल विकास को प्रोत्साहित करना तथा सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करना भविष्य की आर्थिक नीति की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएँ होनी चाहिए। आर्थिक वृद्धि के साथ पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक न्याय को भी विकास प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना आवश्यक है। अतः नई आर्थिक नीति का दीर्घकालीन मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि वह आर्थिक दक्षता, निवेश और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के साथ–साथ रोजगार, समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को किस सीमा तक सुनिश्चित कर पाती है। इस दृष्टि से नई आर्थिक नीति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ रही है, जबकि भविष्य की चुनौती आर्थिक सुधारों के लाभों को अधिक व्यापक, न्यायसंगत और सतत विकास में परिवर्तित करने की है।

संदर्भ सूची

- आचार्य, शंकर, (2012), भारत की अर्थव्यवस्था : नीतियाँ एवं विकास, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
- अग्रवाल, ए. एन., (2011), भारतीय अर्थव्यवस्थाः समस्याएँ एवं संभावनाएँ, विश्व प्रकाशन, नई दिल्ली।
- भल्ला, जी. एस., (2013), भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, मैकमिलन पब्लिशर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली।
- दत्त, रुद्र एवं सुंदरम, के. पी. एम., (2020), भारतीय अर्थव्यवस्था, एस. चाँद एंड कंपनी, नई दिल्ली।
- मिश्रा, एस. के. एवं पुरी, वी. के., (2021), भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुंबई।
- पंडित, वी. एवं चटर्जी, एस., (2015), भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
- पटनायक, प्रकाश, (2018), भारतीय अर्थव्यवस्था और आर्थिक सुधार, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
- सेन, अभिजीत, (2014), भारतीय कृषि और आर्थिक विकास, अकादमिक फाउंडेशन, नई दिल्ली।
- उन्नी, पी. के., (2016), भारत में आर्थिक उदारीकरण, नई दिल्ली।
- वर्मा, एस. एल., (2017), भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण एवं वैश्वीकरण, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
- भारत सरकार, (1991), नई औद्योगिक नीति, उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली।
- भारत सरकार, (विभिन्न वर्ष), आर्थिक सर्वेक्षण, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, (विभिन्न वर्ष), विश्व आर्थिक परिदृश्य, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वाशिंगटन डी.सी.
- दत्त, अमिताभ, (2010), उदारीकरण, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, नई दिल्ली।
- कुमार, अनिल, (2019), भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार एवं विकास, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
- शर्मा, आर. के., (2018), भारतीय अर्थव्यवस्था का समकालीन स्वरूप, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
- सिंह, एस. पी., (2017), भारतीय अर्थव्यवस्थाः आर्थिक सुधार और विकास की चुनौतियाँ, नई दिल्ली।